

# ग्राम वाद

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 मई, 2022

मूल्य 50 पैसे

## आपके नाम चिट्ठी



जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय कदन्न (मोटा अनाज) वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

मोटा अनाज अत्यधिक पोषण गुणवत्ता से युक्त होता है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के वर्ष 2021-22 के बजट में जैविक खेती अपनाने, मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता में वृद्धि करने, फसल उपरांत मूल्य संवर्धन तथा कृषि उत्पादों की घरेलू व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने जैसे कई प्रावधान किए हैं। यह खेती को लाभकारी बनाने के लिए दूरगामी एवं सराहनीय कदम है।

तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने, फल सब्जियों की उपयुक्त किस्में अपनाने, उत्पादन और फसल कटाई की यथोचित तकनीक का प्रयोग करने के लिए किसानों

को सहायता देने के पैकेज प्रावधानों से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार किसानों को जैविक कृषि के साथ उन्नत व लाभकारी कृषि से भी जोड़ने को कृत संकल्पित है।

अब किसान भी समझने लगे हैं कि हमारे खाद्य पदार्थों और खेती में जहरीले रसायनों व कीटनाशकों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जैविक खेती किसानों के लिए समृद्धिदायक है। बड़े पैमाने पर जैविक खेती होने लगेगी तो जैविक उत्पाद उचित दामों में मिलने लगेंगे और उपभोक्ताओं तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी।

राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में किसान जैविक खेती को अपनाकर लाभान्वित हो रहे हैं। उपभोक्ताओं का भी पिछले कुछ वर्षों से जैविक उत्पादों के प्रति रुझान बढ़ा है। देश में स्थानीय स्तर पर जैविक खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और बाजार उपलब्ध कराने की जरूरत है, जिससे जैविक उत्पादों का लाभ जन-जन तक पहुंच सके।

## नुकसानदेह खाद्य पदार्थों के पैकेट पर सीधी चेतावनी आवश्यक

गंभीर बीमारियां पैदा कर रही खाने-पीने की नुकसानदेह चीजों के पैकेट पर ऊपर की ओर ही चेतावनी

कई देशों में यह व्यवस्था लागू की गई है। इसका लोक स्वास्थ्य पर फायदा भी दिखाई देने लगा है। दूसरी तरफ कंपनियों चाहती हैं कि वसा, नमक या चीनी की मात्रा अधिक होने की सूचना साफ तौर पर चेतावनी की तरह लिखे जाने की बजाय हेल्थ स्टार रेटिंग लागू की जाए।



पैकेट पर साफ तौर पर लिखा हो कि इसमें कौनसी नुकसानदेह चीज बहुत ज्यादा है।

यह अध्ययन ऐसे समय पर आया है, जब भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) पैकेटबंद खाद्य चीजों पर चेतावनी की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। एम्स दिल्ली में सामुदायिक मेडिसिन प्रोफेसर डॉ. संजय राय ने कहा, अध्ययन के बाद प्राधिकरण को यह व्यवस्था तुरंत लागू करनी चाहिए। इससे लाखों जानें बचाई जा सकती हैं।

## गैस पाइप में आग लगने पर एजेंसी जिम्मेदार

जिला उपभोक्ता आयोग (प्रथम) में जयपुर जिले के चौमू निवासी लादराम ने परिवार दायर कर कहा कि 31 अगस्त 2012 को गैस सिलेंडर का पाइप कटने से उनकी रसोई में आग लग गई। जिससे एक लाख रुपए का सामान जल गया। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई 2011 को अग्रवाल गैस सर्विस, चौमू से गैस कनेक्शन लिया था, जिसके साथ चूल्हा, गैस पाइप व रेगुलेटर दिया था। ऐसे में गैस पाइप की गुणवत्ता खराब होने से आग लगने की दुर्घटना हुई।

सुनवाई पर गैस एजेंसी संचालक ने कहा कि पाइप की गुणवत्ता के लिए पाइप निर्माता तथा नुकसान की भरपाई के लिए इंग्रोरिस कंपनी जिम्मेदार है। आयोग ने इन दलीलों को सही नहीं माना और फैसले में कहा डीलर बिना चूल्हा एवं गैस पाइप के सामान्यतः गैस कनेक्शन नहीं देता। गैस सिलेंडर का पाइप फटने से आग लगी है, उससे परिवार का नुकसान हुआ है। आयोग ने इसे सेवादोष मानते हुए अग्रवाल गैस सर्विस, चौमू के संचालक को आदेश दिया कि वह परिवार को लादराम को नुकसान की भरपाई के तौर पर 50 हजार रुपए एवं साथ ही मानसिक एवं परिवार व्यय के तौर पर 11 हजार रुपए अलग से चुकाएं।



## 'कट्स' द्वारा 'प्रोस्कोप' परियोजना का शुभारम्भ विकसित किए जाएंगे बारह जिलों में आदर्श जैविक ग्राम

“राज्य में जैविक खेती की प्रचुर संभावनाएं हैं। किसानों को मानव जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जैविक खेती करनी चाहिए। जैविक खेती में किसान अपनी लगन और मेहनत से अच्छा मुनाफा कमा सकता है।” उक्त

विचार 'प्रोस्कोप' परियोजना के शुभारम्भ के अवसर पर मुख्य अतिथि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त जगदीश पारीक ने अपने उद्बोधन में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार व राजस्थान सरकार दोनों ही जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि परियोजना के तहत प्रदेश के बारह जिलों में आदर्श जैविक ग्राम विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पादन के क्षेत्र में पूरे देश में मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 2017 में जैविक कृषि नीति लागू की गई। वर्तमान बजट में घोषित राजस्थान जैविक खेती मिशन एवं जैविक कमोडिटी बोर्ड की स्थापना के निर्णय की प्रशंसा करते हुए उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।



राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था के निदेशक डॉ.ए.एस. बालोदा ने जैविक खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में जैविक उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए जयपुर स्थित दुर्गापुरा कृषि फार्म में लेबोरेटरी

स्थापित की गई है। हनुमान मल ढाका, अतिरिक्त निदेशक, कृषि विभाग ने कहा कि जैविक उत्पादों की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। किसानों को जैविक खेती की ओर अग्रसर करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्राप्त किसान सुरेन्द्र अवाना ने जैविक खेती में हुए नवाचारों के बारे में बताया कि खेती के साथ-साथ पशुपालन, प्रसंस्करण, समन्वित कृषि प्रणाली जैसी अन्य सहायक इकाइयों पर भी काम करना होगा।

कार्यक्रम के दौरान 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने परियोजना का परिचय दिया तथा राजदीप पारीक व अमित बाबू ने परियोजना की आगामी गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। कुलदीप पंवार ने संस्था द्वारा संचालित 'फार्मस प्रोड्यूसर ओर्गेनाइजेशन' परियोजना के तहत की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में किसानों एवं परियोजना सहयोगियों सहित 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

## किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी

देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को केंद्र सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इसमें किसानों को मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि को दोगुना से भी अधिक करने की योजना है। इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है, जिसे जल्द ही केबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।

सरकार की योजना के मुताबिक प्राकृतिक खेती करने वाले ऐसे किसानों को अगले चार साल तक प्रति हेक्टेयर 32,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026 तक प्राकृतिक खेती का रकबा छह लाख हेक्टेयर करना है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राकृतिक खेती वाले उत्पादों की अलग से ब्रांडिंग करने की भी योजना है।



## पत्थर मिट्टी से रोका बारिश का पानी

मेहनतकश आदिवासियों ने देशी तकनीक से सिंचाई का ऐसा जुगाड़ किया कि वे करीब एक हजार बीघा से ज्यादा जमीन पर रबी की फसल ले रहे हैं। प्रदेश के शाहाबाद तहसील क्षेत्र के पूरमपुर के नाथू राम भील की माने तो खेतों में पानी नहीं होने से लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता था।

इस बीच ग्रामीणों ने खान खोह के पहाड़ से बहकर जाने वाले बारिश के पानी को रोककर इस पानी से पेयजल और सिंचाई का रास्ता निकाला। गांव के लोगों ने पत्थरों और मिट्टी के कच्चे कोट में पॉलीथिन का उपयोग कर ऐनिकट तैयार किया। इसके बाद ऐनिकट से गांव तक डेढ़ कि.मी. चौड़ी और करीब तीन कि.मी. लम्बी नाली तैयार की है। इससे गांव की प्यास बुझती है और खेतों में सिंचाई भी होती है।

## सरपंच बेटों ने बदल दी पंचायत की सूरत

राजस्थान के बाड़मेर जिले की बुझतला ग्राम पंचायत आपको साधारण पंचायत से अलग दिखेगी। अत्याधुनिक पंचायत भवन तो सिर्फ शुरुआत है। यहा गांव वालों की परेशानियों को सुलझाने के लिए तीन-तीन कर्मचारी तैनात है।

नोजी देवी के विदेश में काम करने वाले एनआरआई बेटे नवल किशोर गोदारा और टीकू सिंह गोदारा यह सब कर रहे हैं। उन्होंने पंचायत भवन से लेकर पूरी व्यवस्था का कायाकल्प कर दिया है। नोजी देवी को गांव वालों ने निर्विरोध सरपंच बनाया है। उनकी उम्र करीब 80 वर्ष है और वह बिना पढ़ी-लिखी है। गांव वालों का उन पर अटूट विश्वास है।

## 'मनरेगा' बनी लोगों की रोजीरोटी

मनरेगा योजना राजस्थान में एक करोड़ से भी अधिक श्रमिकों की रोजीरोटी का जरिया बनी है। योजना के तहत देश में सर्वाधिक 42.42 करोड़ मानव दिवस सृजन कर प्रदेश अव्वल रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बनी इस योजना की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।

पूरे देश में जहां 3.62 अरब कुल मानव दिवस सृजित किए गए, वहीं अकेले राजस्थान में यह आंकड़ा सर्वाधिक 42.42 करोड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परिवार जोड़ने वाले 5 राज्यों में भी प्रदेश तीसरे स्थान पर है। इस अवधि में राजस्थान में 9.91 लाख परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया।

## कर्मचारी खा गए गरीबों का राशन

प्रदेश में 27,911 सरकारी कर्मचारी ऐसे मिले हैं, जो गरीबों को दिए जाने वाला राशन का सस्ता गेहूं खा रहे हैं। यह सभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सरकारी सेवा से निवृत्त होकर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि विभाग द्वारा जन आधार कार्ड से राशनकार्ड मैपिंग के लिए चलाए गए सघन अभियान के दौरान की गई जांच में यह गड़बड़ी सामने आई। सभी सरकारी कार्मिकों से नियमानुसार 27 रुपए प्रति किलो गेहूं के हिसाब से वसूली कर राशन राजकोष में जमा कराई जाएगी।



## दोगुना हुआ जैविक खेती का रकबा

कोरोना काल में जैविक खेती में खूब नवाचार हुए। देश-प्रदेश से घर लौटे कामगारों ने अपने गांव में जैविक खेती अपना रोजगार की नई राहें तैयार की। इसी का नतीजा है कि जैविक खेती के क्षेत्रफल में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज हुई है। करीब सवा चार लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती कर राजस्थान दूसरे पायदान पर आ गया है।

प्रदेश में जैविक खेती का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीकर के किसान पद्मश्री सुंडाराम वर्मा के अनुसार यहां के किसानों ने नवाचार करते हुए न केवल उद्यानिकी बल्कि परंपरागत फसलों में भी बेहतर उत्पादन प्राप्त कर अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश के कई किसान जैविक खेती कर समृद्धि के द्वार खोल रहे हैं।

## जैविक खेती में नवाचार

में पिछले 5 वर्ष से जैविक खेती कर रहा हूँ, लेकिन दिशा निर्देश के बिना मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। पिछले दो साल से मैं 'कट्स' से जुड़ा हूँ जिससे मुझे जैविक खेती संबंधित बहुत सारी जानकारी मिली। 'कट्स' का सबसे बड़ा जो योगदान रहा वह प्रदेश के जैविक किसानों को एक मंच पर लाकर जोड़ने का रहा। इससे जैविक कृषकों को एक दूसरे को जानने और जैविक खेती में नवाचार जैसी कई जानकारियां प्राप्त हुई हैं। मेरा अनुरोध है कि विजिटिंग के ऐसे प्रोग्राम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में भी करवाएं जिससे जैविक खेती को लाभप्रद बनाया जा सके।

- मांगीलाल शर्मा, बस्सी, जयपुर